



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082020-221178
CG-DL-E-17082020-221178

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2463]
No. 2463]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2020/श्रावण 26, 1942
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2020/SHRAVANA 26, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2020

का.आ. 2780(अ).—यतःकेन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2011, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2011, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 और बोली की अंतिम तारीख तक अनुवर्ती संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना का.आ. 2272(अ), तारीख 20 जुलाई, 2017 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 79 और राष्ट्रीय राजमार्ग 79ए के किशनगढ़-गुलाबपुरा तक के खण्ड 0.000 कि.मी. से 90.000 कि.मी. तक (डिजाइन चैनेज)(रारा 79ए का 0.000 कि.मी. से 35.000 कि.मी. तक और रारा-79 का 15.000 कि.मी. से 69.730 कि.मी.तक विद्यमान चैनेज) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त सेक्शन' कहा गया है)का राराविप फेज-V के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी)आधार पर विकास कर छह लेन का बनाने के लिए मैसर्स किशनगढ़ गुलाबपुरा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड को शुल्क संग्रहण एवं रखने के लिए प्राधिकृत किया था।

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8एके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाशित अधिसूचना का.आ.2272(अ), तारीख 20 जुलाई, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है :

अधिसूचना के पैरा 3 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

3. “यदि परियोजना में विलंब होता है तो करार के अनुसार परियोजना को पूरा करने की तारीख और वास्तविक समापन की तारीख के बीच किसी भी प्रकार का प्रयोगकर्ता शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इस नियम के आशय हेतु अनंतिमरूप से पूरी की गई परियोजना को परियोजना का पूरा होना नहीं माना जाएगा।”

[फा. सं. भाराराप्रा/19025/2015/केयूए/केजी-पैकेज-1/आरएफपी/1/(पीटी-1)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2020

S.O. 2780(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2011, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 and National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2015 and its subsequent amendments upto bid due date, the Central Government, vide notification S.O. 2272(E) dated 20th July, 2017, authorized M/s. Kishangarh Gulabpura Tollway Pvt. Ltd. to collect and retain the fee for the development of Kishangarh- Gulabpura section from km 0.000 (design chainage) to km. 90.000 (design chainage) (existing chainage from km 0.000 to km. 35.000 of NH-79A & from km. 15.000 to 69.730 of NH-79) (hereinafter referred to as the “said section”) of the NH-79A & NH-79 in the state of Rajasthan to Six lane through Public Private Partnership under NHDP Phase-V on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published *vide* S.O. 2272(E) dated 20th July, 2017:-

Para 3 of the notification shall be read as follows:-

“3. No user fee shall be levied for the delayed period between the date of completion as per agreement and the date of actual completion of the project, if it is delayed. For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project.”

[F. No. NHAI/19025/2015/K-U-A/KG-Pkg-1/RFP/1/(pt-1)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.